राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2005

10 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में विकास

2005. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में इस्पात क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकारी, निजी और संयुक्त उपक्रमों के क्षेत्र में, क्षेत्र-वार, इस्पात का वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस्पात का कितना आयात किया गया; और

(घ) देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में क्रूड इस्पात के उत्पादन और क्षमता विस्तार में वृद्धि के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

भारतीय क्रूड इस्पात उत्पादन			क्षमता विस्तार	
वर्ष	मात्रा (मिलियन टन अथवा एमटी में)	गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर	मात्रा (मिलियन टन अथवा एमटी में)	गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर
2011-12	74.29	5.1	90.87	13.0
2012-13	78.42	5.6	97.02	6.7
2013-14	81.69	4.2	101.02	4.1
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)				

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन के आंकड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की श्रेणियों में क्षेत्रवार नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रूड इस्पात का क्षेत्रवार उत्पादन मिलियन टन में (एमटी)			
वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
2011-12	16.47	57.82	74.29
2012-13	16.48	61.94	78.42
2013-14	16.78	64.92	81.69
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)			

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल फिनिश्ड इस्पात के आयात के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

कुल फिनिश्ड इस्पात का आयात मिलियन टन में (एमटी)	
वर्ष	मात्रा
2011-12	6.86
2012-13	7.93
2013-14	5.45
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

(घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है जो एक अनुकूल नीतिगत व्यवस्था प्रदान करती है। तथापि, सरकार ने इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया हैं।

(ii) इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलम्ब करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया हैं।

(iii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने और घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हाल ही में सरकार ने लौह अयस्क पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया है।

(iv) वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में स्टेनलेस स्टील के चपटे उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत की गई है।

***